पेज 03 में...
तोमर के साम्राज्य पर बुलडोजर

साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 28 जुलाई से 03 अगस्त 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 12 में...
बरसात में डूब गया सिस्टम!

वर्ष : 01 अंक : 21 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 10 चप्पल घिस गई, पर हौसले नहीं

समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत हाईस्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर भर्ती में भ्रष्टाचार

परीक्षा और मेरिट सूची का पता नहीं, ठेका एजेंसियां कर रही सौदेबाजी और थमा रही ऑफर लेटर

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

खुलासा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत इन दिनों हाईस्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर की भर्ती हो रही है। समग्र शिक्षा ने इस भर्ती के लिए रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से सात निजी कंपनियों को हायर किया है, यह कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों के आईटी, आईटीस, कंप्यूटर साइंस, पावर, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिलिटि, हेल्थकेयर जैसे अलग-अलग ट्रेड ट्रेनर समग्र शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएगा, समग्र शिक्षा विभाग इन ट्रेनरों को हाईस्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर के तौर पर नियुक्ति देगा। समग्र शिक्षा ने जिन सात कंपनियों को ट्रेड ट्रेनर उपलब्ध कराने का करार किया है वे ठेके के माध्यम से ट्रेड ट्रेनर अभ्यार्थियों से इस नियुक्ति के लिए तीन से चार लाख रुपए रिश्वत लेकर इस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के खेल को अंजाम दे रहे हैं।

JOB OPPORTUNITY
Recruitment of Vocational Trainer (Contractual Basis)
Skill Tree Consulting Limited, invites Applications from candidates with prescribed qualification & experience for deployment as Vocational Trainer in Higher Secondary School in the state of Chhattisgarh. Please See Qualification and Experience criteria below.

IT/ITeS – 142
BALOD-4, BALODABAZAR-14, BALRAMPUR-8, BASTER- 3, BEMETARA-8, BILASPUR-11, DHAMTARI-3, DURG-5, JANJGIR - CHAMPA-11, JASHPUR-4, KAWARDHA-6, KORBA-4, KORIYA-3, MANENDRAGARH-3, MUNGELI-3 RAIGARH-6, RAIPUR-11, RAJNANDGAON-7,SAKTI-7 ,SARANGARH-BILAIGARH-6, SURAJPUR-8, SURGUJA-7
Bachelor of Engineering / Technology in Computer Science / Information Technology OR Master of Computer Application (MCA) OR Master of Science (Computer Science/IT) OR NIELIT "B" Level Certificate. Desirable: Knowledge and skills in CRM software.
Exp : min 1 Year of Working Experience is required.

BFSI – 105
BALODABAZAR-2, BALRAMPUR-6, BEMETARA- 7,BILASPUR-1, DHAMTARI-5, DURG-1, GARIABAND-5, GOURELA PENDRA MARVAHI-1,

व्यावसायिक शिक्षक भर्ती का बाजार

ढाई-तीन लाख दो और बन जाओ VT समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर 'मेला'

राजधानी रायपुर के समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर इन दिनों एक अजीब-सा मेला लगा है। यह कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि ऐसा मेला है जहां टिकट की जगह ढाई से तीन लाख रुपये देने पड़ते हैं। यह है सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक (VT) भर्ती का 'महाकुंभ', जहां ठेका कंपनियां खुलकर "पैसा दो, नौकरी लो" का खेल खेल रही हैं।

इस भर्ती के लिए ट्रेड अभ्यार्थियों से बी लेवल प्लस एक साल का अनुभव मांगा गया है इसके बाद इन ट्रेनर अभ्यार्थियों से लिखित परीक्षा और मेरिट सूची के आधार पर इनका चयन करना है, लेकिन कंसल्टिंग कंपनियों द्वारा आवेदित अभ्यार्थियों की न ही परीक्षा ली जा रही है और न ही मेरिट सूची तैयार की जा रही है। सीधे पर भ्रष्टाचार के इस खेल को अंजाम देने के लिए अभ्यार्थियों को ऑफिस बुलाकर तीन से चार लाख रुपए लिए जा रहे है। आपको बता दें कि समग्र शिक्षा द्वारा पहले भी एनजीओ और एजेंसियों को बिना नियमों के तहत काम देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कई एनजीओ और एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बावजूद इसके अब जिन - जिन एजेंसियों द्वारा वोकेशनल ट्रेनर मांगा गया है उन कंपनियों पर लेनदेन कर वोकेशनल ट्रेनर भर्ती का आरोप लग रहा है।

क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आईटी, कंप्यूटर साइंस, पावर, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग और रिटेल जैसे ट्रेड शुरू करने के लिए समग्र शिक्षा विभाग ने 2025 में 7 निजी कंपनियों का चयन किया। ये कंपनियां हाईस्कूलों के लिए ट्रेनर उपलब्ध कराती हैं।

नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी

- लिखित परीक्षा और मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई।
- कंपनियों ने ऑफिस बुलाकर 3 से 4 लाख रुपये लेकर सीधी नियुक्ति दी।
- 10 रुपये के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट करवा कर युवाओं को बांध दिया।
- लगभग 40 हजार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़।

652 स्कूलों में ट्रेनर नहीं, 121 स्कूलों में सीधे ठेका

इस साल 652 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। लैब और लाइब्रेरी तैयार हो गईं, लेकिन भर्ती रोक दी गई। वहीं, 121 स्कूलों का काम स्किल ट्री और इंडस एडुट्रेन को बिना निविदा सीधे दे दिया गया। कंपनियों के तार एक ही प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़े होने की चर्चा है।

न नियम का डर, न पारदर्शिता का बंधन

बस जेब में नोट हो, तो हेल्थकेयर, आईटी, प्लंबर, ब्यूटी एंड वेलनेस किसी भी ट्रेड में शिक्षक की कुर्सी आपकी। समग्र शिक्षा, जो कागजों में शिक्षा को समग्र बनाने का वादा करती है, जमीनी हकीकत में ठेकेदारों की जेब भरने का जरिया बन चुकी है। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है "ठेका कंपनी के दलाल खुलेआम कहते हैं – पैसा दो और VT बन जाओ। समग्र शिक्षा का नारा था – सबके लिए शिक्षा। अब नारा बदल गया है – सबके लिए वसूली। अगर जेब खाली है, तो पढ़ाई नहीं, धरना देने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में अब 'नोट्स' नहीं, सिर्फ 'नोट' चलते हैं।"

भर्ती घोटाले में पैसे के लेनदेन की शिकायत के बाद टेबल से भागे कर्मचारी

जिनके पास पैसे नहीं वो धरने पर बैठे

धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि 1300 से अधिक पदों के लिए कंपनियों ने रेट फिक्स कर रखे हैं—2 से 3 लाख रुपये प्रति सीट। कोई कहता है "मैंने ढाई लाख दिए", तो कोई शिकायत करता है "तीन लाख देने के बाद भी सिर्फ वादा मिला।" और जिनके पास देने को पैसे नहीं, वे हफ्तों से सड़क पर धरना देने को मजबूर हैं।

कोरोना बोनस अंक भी धरे रह गए

अभ्यर्थी अजय त्रिपाठी और योगेश देवांगन कहते हैं, "भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही हमने आवेदन, दस्तावेज सब जमा किए। सरकार ने कोरोना योद्धाओं को 10% बोनस अंक देने का आदेश जारी किया था, पर ठेका कंपनियों ने उस नियम को भी कूड़े में फेंक दिया। स्वास्थ्य मंत्री का पत्र भी बेकार साबित हुआ। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था कि किसी NGO या ठेका कंपनी के जरिए भर्ती नहीं होगी, लेकिन यहां तो वही कंपनियां सब कुछ चला रही हैं।"

जांच का भरोसा पर अभ्यर्थियों में गुस्सा

समग्र शिक्षा के वित्त अधिकारी (प्रभारी एमडी) रामकिशोर शर्मा का कहना है, "शिकायतें मिली हैं, जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।" लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्यालय में ताला जड़ देंगे। अब ये ताला खुलवाने के लिए भी क्या कोई रेट तय होगा?"

भ्रष्टाचार का आरोप, NSUI ने की जांच मांगी

छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत हुई व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल टीचर) भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने विभाग को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि कहा कि बिना मेरिट और परीक्षा के, 10 रुपए के स्टांप पेपर पर जबरन एग्रीमेंट कराकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और प्रत्येक चयन के बदले 3 से 4 लाख रुपये वसूले गए। ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग 40 हजार युवाओं के साथ धोखा हुआ है, मार्कशीट और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा सामने आया है और अधिकारियों के रिश्तेदारों को सीधे ज्वॉइनिंग दी गई। कोविड काल में सेवा देने वाले नर्सिंग, आईटी, हेल्थ ट्रेड के युवाओं को 10 प्रतिशत प्राथमिकता का लाभ भी नहीं मिला। एनएसयूआई ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने, मेरिट सूची को सार्वजनिक करने और सीबीआई व ईओडब्ल्यू से जांच की मांग की है। संगठन ने 28 जुलाई तक अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो समग्र शिक्षा कार्यालय का तालाबंदी आंदोलन और प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।

HSRP लगाने में सुस्त रफ्तार, सिर्फ 9% वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने का काम बेहद धीमा है। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में इन प्लेटों को लगाना अनिवार्य है। इसके लिए जून 2025 की अंतिम तारीख तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर सितंबर 2025 कर दिया गया है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 28 जिलों में पंजीकृत 52 लाख 48 हजार 476 वाहनों में से 22 जुलाई 2025 तक सिर्फ 4 लाख 61 हजार 913 वाहनों में ही HSRP लगाई जा सकी है। यानी कुल वाहनों का केवल 8.8 फीसदी हिस्सा ही अपडेट हुआ है। राजधानी रायपुर में पुलिस लगातार चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रही है। अब तक 50 से ज्यादा वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है।

HSRP की स्थिति

(1 दिसंबर 2024 से 22 जुलाई 2025 तक)

कुल पंजीकृत वाहन	:	52,48,476
HSRP ऑर्डर	:	8,23,636
HSRP लग चुके	:	4,61,913
प्रतिशत	:	8.8%

सबसे ज्यादा प्लेट रायपुर (1.51 लाख), दुर्ग (86,809) और बिलासपुर (41,168) जिलों में लगी हैं। सबसे कम प्रगति नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जिलों में हुई है।

पुलिस की सख्ती और अपील

ट्रैफिक एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला ने बताया, "समय सीमा जून में समाप्त हो चुकी है। अब वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में 60 फिटमेंट सेंटर बनाए गए हैं, जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आसानी से HSRP लगवाई जा सकती है।" HSRP के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि यह नंबर प्लेट छेड़छाड़ और डुप्लीकेट से सुरक्षित है। चोरी के बाद नंबर बदलना संभव नहीं होगा। दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए इसकी फीस 365 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 720 रुपये तय की गई है। फिलहाल जिन वाहनों में HSRP नहीं लगी है, उन पर दोपहिया के लिए 1000, चारपहिया के लिए 2000 और भारी वाहनों के लिए 3000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है।

तोमर बंधुओं के साम्राज्य पर बुलडोजर

सूदखोरी के गढ़ पर सरकार का वार

रायपुर। ब्लैकमेलिंग और सुदखोरी के धंधे से राजशाही जिंदगी जीने वाले तोमर बंधुओं के साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद राजधानी रायपुर में यह पहली बड़ी कार्रवाई है, जिस ऑफिस को ध्वस्त किया गया है उसे रोहित तोमर ने अपनी पत्नी भावना के नाम से खोला था और यहीं से सूदखोरी का काम करते थे। रोहित और वीरेंद्र तोमर पिछले 2 महीने से फरार हैं, दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। वहीं, इस कार्रवाई पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने से कोई कानून से बड़ा नहीं हो जाता। अपराधी तोमर ने अनेक लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा कि बुलडोजर तो चलेगा। हम विपक्ष में थे तब भी स्पष्ट थे। आज जनसेवा के लिए शासन में हैं तब भी स्पष्ट हैं। डिप्टी सीएम ने आगे लिखा तब माइक से अपराधियों और आताताइयों को बोलते थे। आज हमारे नगर निगम का बुलडोजर बोलता है। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे जितना बड़ा तुर्रम खां हो। तोमर बंधु हों या जिहादी बंधु हों। आतंक का फन फैलाओगे तो फन कुचलने का हुनर भी सरकार को मालूम है।

कानून से कोई बड़ा नहीं : विजय शर्मा

सोशल मीडिया में वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रोहित तोमर का कई मंत्रियों-विधायकों और राजनीतिक महकमे के बड़े नेताओं के साथ फोटो है, जिससे वह अपनी शाख राजनीतिक महकमे में बताता था। वह अपनी इस पृष्ठभूमि को समाजसेवा से जोड़ते हुए अपराध को ढंकने की कोशिश करता था। इसी को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी नेता या मंत्री के साथ फोटो खिंचाने से उसका अपराध ढक नहीं जाएगा, कानून से कोई बड़ा नहीं, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई तय है, जो अपने आपको कानून से ऊपर समझेगा उसका हाल ऐसा ही होगा।

फन फैलाओगे तो सरकार कुचल देगी - अरूण साव

कोई भी अपराधी अपने आप को तुर्रम खां समझेगा उसके साथ ऐसा ही हाल होगा चाहे वह तोमर बंधु हों या जिहादी बंधु। आतंक का फन फैलाओगे तो सरकार फन कुचल देगी। यह बुलडोजर सरकार की जुबान है।

ऐसे शुरू हुई तोमर बंधुओं पर कार्रवाई

- नगर निगम की टीम रविवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ भाठागांव पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया। यह दफ्तर रोहित तोमर ने पत्नी भावना तोमर के नाम से खोला था। यहीं से सूदखोरी, धमकी और अवैध वसूली का नेटवर्क चलता था।
- 10 दिन पहले पुलिस ने भावना तोमर को गिरफ्तार किया था। भावना शुभकामना वेंचर्स कंपनी के नाम से जमीन सौदों का काम करती थी। उस पर आरोप है कि 3 लाख का कर्ज देकर पीड़ित की 15 लाख की कार गिरवी रखी, 5 लाख लौटाने के बाद भी कार नहीं लौटाई और 10 लाख की अतिरिक्त मांग की। पुलिस ने कार, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए हैं।
- रोहित और वीरेंद्र तोमर दो महीने से फरार हैं। 18 जुलाई को पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उद्घोषणा जारी कर इन्हें फरार घोषित कर दिया। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

तोमर बंधुओं का आपराधिक रिकॉर्ड

- सूदखोरी, धमकी, अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के 6+ केस।
- निगरानी गुंडा बदमाश की लिस्ट में नाम।
- राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, पुरानी बस्ती, कोतवाली और गुडियारी में 9 से ज्यादा केस दर्ज।
- गोल्डन मैन नाम से कुख्यात और लंबे समय से लोगों को डराकर पैसे वसूलते रहे

ये हो तोमर बंधुओं का तरीका

- भारी ब्याज पर कर्ज।
- कोरे स्टांप और चेक पर जबरन साइन।
- रकम लौटाने के बाद भी संपत्ति और कार हड़प लेना।
- धमकी देकर जमीन औने-पौने दाम में खरीद लेना।
- एक केस में 10 लाख का कर्ज 1 करोड़ 10 लाख बन गया। पीड़ितो का कहना है कि उनके डर से लोग शिकायत तक नहीं कर पाते थे। अब कार्रवाई के बाद थानों में पीड़ित खुलकर सामने आ रहे हैं।

रावतपुरा मेडिकल कॉलेज घूसकांड: 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रायपुर। रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, नवा रायपुर से जुड़े मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि आरोप गंभीर हैं और सभी आरोपी अन्य राज्यों के निवासी हैं, ऐसे में उनके फरार होने की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक दौर में है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। जिनकी जमानत याचिका खारिज हुई है- अतुल कुमार तिवारी (कॉलेज डायरेक्टर), डॉ. मंजप्पा सी.एन., डॉ. चित्रा एम.एस., डॉ. सतीशा ए.।

55 लाख की घूस का मामला : सीबीआई की FIR के मुताबिक, 55 लाख रुपये की रिश्वत हवाला चैनल के जरिए ट्रांसफर की गई थी ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की निरीक्षण रिपोर्ट कॉलेज के पक्ष में आ सके। सीबीआई ने निरीक्षण टीम को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा था। जांच में सामने आया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई मेडिकल कॉलेजों में इसी तरह मान्यता के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है।

सीडीकांड में अगली सुनवाई 26 अगस्त को

इसी दिन अदालत ने कथित सेक्स सीडीकांड से जुड़े मामले की सुनवाई भी टाल दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाई गई रिविजन याचिका पर अब सुनवाई 26 अगस्त को होगी। इस मामले में आरोपी बनाए गए कैलाश मुरारका, विजय भाटिया, विनोद वर्मा और विजय पंड्या के आवेदन पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। सीबीआई ने दोनों मामलों में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि इस मामले में भूपेश बघेल को पहले आरोपमुक्त किया जा चुका है, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका (रिविजन) दायर की है।

रायपुर-दुर्ग में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

वॉट्सऐप पर फोटो दिखाकर बुलाते थे ग्राहक

रायपुर। रायपुर पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर से संपर्क में आने वाले ग्राहकों को वॉट्सऐप पर युवतियों की फोटो भेजकर सौदा तय करते थे। इसके बाद उन्हें प्रोफेसर कॉलोनी स्थित किराए के मकान में बुलाया जाता था, जहां लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा था। यह कार्रवाई पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में हुई। 23 जुलाई को पुलिस ने एक मुखबिर को ग्राहक बनाकर पैसे के साथ घर भेजा। डील तय होने के बाद मुखबिर के इशारे पर टीम ने दबिश दी। मौके से आपत्तिजनक सामान मिला और एक युवती सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वहां मौजूद एक पीड़ित युवती को भी छुड़ाया। आरोपियों के मोबाइल से चैट और पैसों के लेनदेन के सबूत भी बरामद हुए हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी आकाश साहू (39) सड्डू का रहने वाला है। वह अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर ग्राहकों को बुलाता और उनसे देह व्यापार कराता था। इसी नेटवर्क में शामिल कृषाणु दास (42) शंकर नगर निवासी है, जिसके समता कॉलोनी, कटोरा तालाब और खम्हारडीह में तीन स्पा सेंटर हैं। वहीं से ग्राहक आते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, जबरन देह व्यापार में फंसी एक पीड़िता को भी छुड़ाया गया।

छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन चाकू की बिक्री पर रोक

रायपुर। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन मंगाए गए चाकू से हत्या की वारदात सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन चाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फ्लिपकार्ट ने राज्य में धारदार हथियारों की डिलीवरी बंद कर दी है। जांच में सामने आया कि अपराधी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए स्प्रिंग और डिजाइनर चाकू मंगाकर हत्या और हत्या के प्रयास जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने बताया कि यह रोक अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अहम कदम है। अब अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हाल ही में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या के मामले में यह खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने हत्या में जिस चाकू का इस्तेमाल किया, उसे ऑनलाइन मंगवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने फ्लिपकार्ट और कुरियर कंपनी के छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

रायपुर के मल्टीप्लेक्स में पहली बार गूंजे भजन-कीर्तन

रायपुर। भारत में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला जब किसी आधुनिक मल्टीप्लेक्स में शो शुरू होने से पहले हरे राम-हरे कृष्ण के भजन-कीर्तन गूंजे। शनिवार को रायपुर के एक मॉल में 'महावतार नरसिम्हा' फिल्म का शो देखते हुए इस्कॉन के 277 भक्तों ने पारंपरिक वेशभूषा, मृदंग और करताल के साथ कीर्तन किया। भक्त धोती-कुर्ता पहनकर, माथे पर तिलक और गले में कंठी माला डालकर पहुंचे। स्पाइडरमैन की पोशाक पहना एक युवक भी इस कीर्तन में शामिल था। भजनों और जयकारों से पूरा माहौल आध्यात्मिक हो गया। इस्कॉन से जुड़े भक्तों ने कहा कि यह फिल्म सनातन संस्कृति और मूल्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करती है। भक्त आयुष का कहना है, "आज ऐसी फिल्में बहुत कम बन रही हैं। यह युवाओं को सनातन धर्म के मूल विचार से जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है।" 25 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को बुक माई शो पर 9.8 रेटिंग मिली है और सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। 'महावतार नरसिम्हा' प्रह्लाद और भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कथा पर आधारित है।

आबकारी आरक्षक परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी हुए अव्यवस्था के शिकार

खैरागढ़। जिले में आयोजित व्यापम की आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा खैरागढ़ में अव्यवस्था और भ्रम का शिकार हो गई परीक्षार्थी।।परीक्षा का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक था, लेकिन प्रवेश के लिए अंतिम समय 10:30 बजे तय था।।परीक्षार्थियों का आरोप है कि वे सुबह 9 बजे से पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे।।लेकिन उन्हें ड्रेस कोड के नाम पर टी-शर्ट या साड़ी बदलने को कहा गया।। जब वे कपड़े बदलकर लौटे 10:30 का समय बीत चुका था और गेट बंद कर दिया गया।। सबसे अधिक हंगामा पीएम श्री बख्शी स्कूल, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, रानी रश्मिदेवी कॉलेज और डाइट खैरागढ़ परीक्षा केंद्रों में हुआ।। एक महिला को साड़ी पहनने पर परीक्षा से रोक दिया गया।। साड़ी में आई महिला ने बताया कि मैं अपने ससुराल में रहती हूं जहां मुझे सलवार सूट पहनने की अनुमति नहीं है।। मैंने अपने सास-ससुर से छुपकर पढ़ाई की तैयारी की और आज परीक्षा देने आई थी,लेकिन सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी।।करीब 100 से अधिक अभ्यर्थियों के परीक्षा से वंचित होने के बाद युवक युवतियां और महिलाएं परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करो के नारे लगाए और सुबह करीब 11:30 बजे सिविल लाइंस मेन रोड स्थित कलेक्टर बंगले का घेराव किया।

छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टा केस हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में चल रहे समान मामलों के साथ जोड़ते हुए अपने पास ट्रांसफर कर लिया है।

क्या है मामला

राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि कई ऑनलाइन सट्टा एप छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं।

इन एप्स के माध्यम से करोड़ों रुपये का अवैध सट्टा न केवल प्रदेश बल्कि देशभर में संचालित हो रहा है। इसके कारण कई लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन, गृह सचिव और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट में यह भी कहा गया कि इन एप्स के कारण प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और नैतिक गिरावट आ रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

इसी बीच देश के अन्य हिस्सों से भी ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। शीर्ष अदालत ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका को भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया।

नक्सल प्रभावित इलाकों में लगेंगे 400 नए BSNL टावर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने रविवार को रायपुर में घोषणा की कि इन क्षेत्रों में 400 नए BSNL टावर लगाए जाएंगे।

डॉ. शेखर ने कहा कि सुरक्षाबलों और वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद इन टावरों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया, "बीएसएनएल आज देश में उच्च गुणवत्ता की 4जी सेवाएं दे रहा है। इस विस्तार से अंतिम गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का मिशन साकार होगा।" रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (P M A Y), पीएम आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के क्रियान्वयन पर संतोष जताया और कहा कि इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और आवास में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। डॉ. शेखर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।

छत्तीसगढ़ में घुसपैठ रोकने के लिए हर गांव में बनेगा 'नागरिक रजिस्टर'

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अब अवैध विदेशी नागरिकों की घुसपैठ रोकने के लिए हर गांव में 'नागरिक रजिस्टर' तैयार करने जा रही है। इस रजिस्टर में गांव में बसने वाले पुराने निवासियों, नए आने वालों और बाहर जाने वाले लोगों की जानकारी दर्ज की जाएगी। पंचायत स्तर पर यह रजिस्टर फिजिकल फॉर्म में रखा जाएगा।

उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, "हम पंचायतों में ऐसा रजिस्टर बनवा रहे हैं जिससे यह साफ हो सके कि कौन पहले से रह रहा है और कौन नया आया है। यह कदम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है।" राज्य में हाल ही में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया है और करीब 2,000 पाकिस्तानी वीज़ाधारकों की निगरानी की जा रही है। घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद को लेकर देशभर में बढ़ती चिंता के बीच यह फैसला लिया गया है। कवर्धा जिले के नेवारी गांव के सरपंच सेवराम पात्रे ने कहा कि पहले बाहर से आने वालों को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब रजिस्टर बनने से बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय योजनाओं का गलत फायदा लेने पर रोक लगेगी।

27 साल बाद भी प्रेरणा हैं बलिदानी लांस नायक कौशल यादव

कारगिल में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर हुए शहीद

भिलाई। कारगिल विजय दिवस पर छत्तीसगढ़ के वीर सपूत बलिदानी लांस नायक कौशल यादव को याद किया गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का रास्ता चुनने वाले कौशल यादव ने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। 25 जुलाई 1999 को द्रास सेक्टर के जुलु टॉप (5100 मीटर ऊंचाई) पर हुए भीषण मुकाबले में उन्होंने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और खुद वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भिलाई में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कौशल यादव 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स में भर्ती हुए। 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान उन्हें द्रास सेक्टर के जुलु टॉप को दुश्मनों से मुक्त कराने का जिम्मा मिला। यह इलाका बेहद दुर्गम था—5100 मीटर की ऊंचाई, 15 डिग्री ठंड, खड़ी चट्टानें और गोलियों की बरसात। कौशल यादव ने जान की परवाह किए बिना दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया, ग्रेनेड फेंकते और नजदीकी फायरिंग करते हुए 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस मुकाबले में वे खुद गंभीर रूप से घायल हो गए और बलिदान हो गए। उनकी मां धनवंता देवी आज भी हर साल स्मारक स्थल पर जाती हैं। वे कहती हैं, "ऐसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई।

खेल-खेल में काल के गाल में समाया युवक

खैरागढ़। शनिवार को खैरागढ़ के इतवारी बाजार में आयी बाढ़ के दौरान लापता हुआ 16 वर्षीय युवक अमित यादव का शव रविवार शाम लगभग 5.30 बजे इतवारी बाजार के डोंगा नाले के अंतिम छोर से बरामद हुआ।। अमित शीतला मंदिर के पास स्थित एक मोटर गैराज की छत से खेल-खेल में बाढ़ के पानी में छलांग लगाकर दोस्त अक्कू के साथ अटखेलियाँ कर रहा था, तभी दोनों बाढ़ के तेज बहाव में बह गये।। अक्कू किसी तरह कुछ दूर बाद बाढ़ के तेज बहाव से बच निकला लेकिन अमित देखते ही देखते बाढ़ के पानी में लापता हो गया।। रविवार सुबह 5 बजे से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो दिनभर चलता रहा।। शाम तक़रीबन 5.39 बजे इतवारी बाजार स्थित मुर्गा मार्केट इलाके में टीआई अनिल शर्मा व यातायात प्रभारी शक्ति सिंह स्वयं बांस लेकर नाले में उतरे और तलाश में जुटे रहे,इसी दौरान ग्राम बल्देवपुर निवासी एक युवक जो सब्जियां खरीदने आया था,ने मानवीय भाव दिखाया और अपने कपड़े उतार कर स्वयं ही लाश ढूंढने नाले में उतरा और अंततः पुलिस अधिकारियों के सहयोग से युवक के शव को नाले से बरामद किया गया।।

गांव की गलियों से इंटरनेशनल ट्रैक तक

भारत का सबसे तेज धावक बना छत्तीसगढ़ का अनिमेष

जशपुर जिले के छोटे से गांव घुइटांगर की पगडंडियों पर दौड़ने वाला एक बच्चा अब दुनिया के ट्रैक पर भारत का नाम रोशन कर रहा है। 5 जुलाई 2025 को ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में 100 मीटर दौड़ को 10.18 सेकंड में पूरा कर अनिमेष कुजूर ने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। इस प्रदर्शन के बाद 21 वर्षीय अनिमेष को देश का सबसे तेज धावक माना जा रहा है।

छोटे गांव से बड़ी उड़ान

अनिमेष का बचपन जशपुर के घुइटांगर गांव में बीता। खेतों और गलियों में दौड़ लगाते हुए उनकी शुरुआत हुई। जहां भी माता-पिता की पोस्टिंग रही—महासमुंद, कवर्धा, कांकेर—वहां छोटी-छोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर जीतते रहे। छठवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हुई। यहीं खेल और अनुशासन दोनों सीखे। कोरोना काल में जिला स्तर पर 100, 200, 400 मीटर के साथ लंबी और ऊंची कूद में गोल्ड जीतने के बाद उनका चयन वेस्ट जोन के लिए हुआ। शुरुआत में न ट्रेनिंग की सुविधाएं थीं, न स्पाइक शूज। चार दिन पहले ही पिता ने उन्हें पहला स्पाइक शूज दिलाया। इसके बाद भी अंडर-18 नेशनल में छत्तीसगढ़ का इकलौता खिलाड़ी रहते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। यही वह मोड़ था जब परिवार ने उन्हें पूरी तरह खेल के रास्ते पर बढ़ने का फैसला लिया। 2022 में बिलासपुर में अंडर-23 गोल्ड जीतने के बाद अनिमेष को रिलायंस फाउंडेशन में ट्रेनिंग का मौका मिला, जहां विदेशी कोच मार्टिन ओवेंस की देखरेख में उनकी रफ्तार निखरी। ग्रीस में हुई रेस के बाद दूसरे दिन जब अनिमेष ने फोन कर घरवालों को बताया कि वह नेशनल रिकॉर्ड बना चुके हैं, तब परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डीएसपी मां रीना नीलम कुजूर कहती हैं, "बेटा भारत का सबसे तेज धावक बन गया, यह सुनकर गर्व और खुशी से आंखें भर आईं। बचपन से ही वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा रहा है।"

अनुशासन और मेहनत बना सहारा

सैनिक स्कूल का अनुशासन, कठिन मेहनत और माता-पिता का सहयोग अनिमेष की सफलता का राज है। पिता और मां दोनों का कहना है कि जो सपना वे खुद अपने खेल जीवन में नहीं पूरा कर पाए, वह बेटे ने पूरा कर दिखाया।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

संसद में देशहित के मुद्दों पर चुप्पी क्यों?

संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष के बीच खींचतान के बाद जैसा हंगामा देखा गया, वह एक तरह से अपेक्षित था। जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आई, उससे एक बार फिर यही लगता है कि जनहित से जुड़े मसलों पर बातचीत के बजाय संसद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की जगह बनती जा रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक सदन में बहस के लिए मुद्दों का चुनाव करती है और ऐसे में जनहित तथा राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों की उपेक्षा की जाती है, वहीं सरकार यह मानती है कि विपक्ष नाहक ही सदन को बाधित कर जरूरी कामकाज में अड़चन डालता है। इसमें दोराय नहीं कि जब तक किसी मुद्दे पर लोकसभा या राज्यसभा में बहस नहीं होगी, तब तक जनहित के सवाल उपेक्षित रहेंगे, लेकिन इस क्रम में ऐसी स्थिति पैदा होने को कैसे सही ठहराया जा सकता है कि सदन में विचार-विमर्श के बजाय एकतरफा बातचीत होने लगती है और उसी के आधार पर नियम-कायदे भी तय हो जाते हैं।

गौरतलब है कि करीब एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से मुख्य रूप से पहलगाम हमले, आपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, मणिपुर के हालात और चीन के रुख आदि मसलों पर चर्चा कराने पर जोर दिया गया। हालांकि सरकार ने दावा किया कि वह इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो यह समझना मुश्किल है कि फिर खींचतान और हंगामे के हालात यहां तक कैसे पहुंचे कि सदन को स्थगित करने की नौबत आई। सरकार और विपक्ष के बीच संसद में आमने-सामने की बहस और सवाल-जवाब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

अगर सरकार को लगता है कि वह विपक्ष की मांग के मुताबिक सभी विषयों पर बहस के लिए तैयार है, तब आखिर संसद में हंगामे की नौबत क्यों आती है? क्या ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल सकता जिसमें सदन बाधित न हो और संसद का कामकाज सुचारु रूप से चले? विपक्ष अगर चर्चा की मांग करता है, तो सदन को सामान्य रूप से संचालित होने देना और जरूरी मुद्दों पर बहस को लोकतांत्रिक निष्कर्ष तक ले जाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है?

देश और नागरिकों के हित से जुड़े व्यापक महत्त्व के सवालों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं होगी तो और कहां होगी? मगर सरकार और विपक्ष जिन मुद्दों पर टकराव की मुद्रा में आ जाते हैं, उसमें यह कैसे तय होगा कि किस सवाल को बहस की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए? सही है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और उसके बाद की परिस्थितियां राष्ट्रीय महत्त्व का मसला है। इसी तरह बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिस तरह के सवाल उठे हैं, उस पर भी तत्काल बात होनी चाहिए।

मणिपुर में भी लंबे समय से जिस तरह हिंसा के हालात बने हुए हैं, उसका समाधान भी तुरंत खोजने की जरूरत है। मगर क्या सदन में इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित है? विडंबना है कि हंगामे की शोर में जरूरी मुद्दों पर बहस नहीं हो पाती और सदन स्थगित हो जाता है। इस संदर्भ में सदनों की कार्यवाही पर एक दिन के खर्च और उसके बेकार जाने के मसले पर भी काफी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष को मिल कर यह सोचने की जरूरत है कि बाधित सदन में जनहित के सवालों के लिए कितनी जगह बची है।

राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र कितनी हो?

शेखर गुप्ता

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर हो जाने और युवाओं के लिए जगह खाली करने के बारे में सोचना चाहिए। आप यह मत सोचने लग जाइए कि उन्होंने कोई अवांछित बात कह दी है। वैसे कोई प्रतिक्रिया देने में सावधानी बरतना लाजिमी है, क्योंकि भाजपा-संघ रिश्तों के मामलों में नरेंद्र मोदी हमेशा अपवाद रहेंगे।

मोदी 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, और इससे छह दिन पहले भागवत भी 75 के हो जाएंगे। इन संदर्भों के मद्देनजर भागवत के बयान को मोदी के लिए किसी संकेत के रूप में लेना उसमें कुछ ज्यादा पढ़ लेने जैसा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि मराठी में दिए इस भाषण में भागवत ने सिर्फ 75 की उम्र में रिटायर होने वाली बात हिंदी में कही थी!

2005 में संघ प्रमुख सुदर्शन से मेरी दो किस्तों में बातचीत हुई थी, जिसमें सुदर्शन ने तब 77 के हो चुके आडवाणी और 80 के हो चुके वाजपेयी से युवाओं के लिए जगह खाली करने को कहा था। मैंने उन्हें याद दिलाया था कि वाजपेयी ने अपने रिटायर होने की अफवाहों को यह कहकर खारिज किया है कि न टायर्ड हूं, न रिटायर्ड हूं।

उस समय भाजपा पर अटल- आडवाणी की जोड़ी की पकड़ मजबूत थी और उनकी कुर्सियों का कोई दावेदार नहीं था, इसलिए सुदर्शन की आलोचना हुई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भाजपा-संघ के नजरिए से उनकी गलती सिर्फ यह थी कि उन्होंने गलत समय पर वह बयान दिया था।

इससे पिछले साल ही पार्टी आम चुनाव में हार गई थी और उसे उस समय उत्तराधिकार के किसी संघर्ष में उलझना नहीं था। लेकिन उनके बयान ने रास्ता साफ कर दिया था। संभावित उत्तराधिकारियों की एक पूरी कतार उभरने लगी : राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सबसे उल्लेखनीय, नरेंद्र मोदी। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व को लेकर अमेरिकी शैली की होड़ की शुरुआत करवा दी। 2012 में मोदी उस होड़ में आगे निकल गए।

आप भाजपा-संघ को पसंद करते हों या नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में उनका 'एचआर सिस्टम' (मानव संसाधन व्यवस्था) सबसे मजबूत और योग्यतापरक है। भारत के राजनीतिक इतिहास में जितनी पार्टियां उभरीं, उनमें भाजपा ही ऐसी है, जिसमें न्यूनतम दलबदल हुआ है।

कल्याण सिंह या येदियुरप्पा सरीखे कुछ नेता पार्टी से अलग हुए, लेकिन वापस भी लौटे। अलग होने वाले कुछ नेता बियाबान में खो गए, जैसे शंकरसिंह वाघेला या बलराज मधोक आदि। उन्हीं दशकों में कांग्रेस कई बार टूटी और कभी-कभी तो ऐसा लगा कि इससे टूटे गुटों के नाम में कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए वर्णमाला के अक्षर भी पूरे नहीं पड़ेंगे। जनता पार्टी, समाजवादी या लोक दल का भी यही हश्र हुआ।

भाजपा में कम-से-कम शीर्ष स्तर पर पारिवारिक उत्तराधिकार का भी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इसके जाने-माने संस्थापकों और वरिष्ठों के कई वंशज पार्टी में प्रमुख पदों पर बैठे हैं, लेकिन सत्ता हस्तांतरण से ज्यादा यह किसी के बच्चे को 'जगह देने' जैसा मामला रहा।

आप देख सकते हैं कि अटल-आडवाणी के दौर में भी काफी युवा मुख्यमंत्रियों को चुना गया : वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नरेंद्र मोदी। इन सबकी औसत उम्र करीब 49 साल थी। युवा प्रतिभा की पहचान और उसे मजबूती देने का यह चलन भाजपा के अध्यक्ष के चयन के मामले में और उल्लेखनीय दिखता है।

2002 में वेंकैया नायडू 53 साल की उम्र में भाजपा अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह 54 की उम्र में, नितिन गडकरी 48 की उम्र में तो अमित शाह 49 की उम्र में अध्यक्ष बने। जबकि इस पूरी अवधि में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहीं। बीच में बहुत थोड़े समय के लिए राहुल गांधी अध्यक्ष बने और अब मल्लिकार्जुन खरगे हैं, जो 80 के हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस में कई युवा प्रतिभाएं मुरझा गईं। इन दोनों पार्टियों के 'एचआर सिस्टम' पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

भाजपा में इस 'सिस्टम' का 2014 के बाद भी पालन किया गया है। जेपी नड्डा ने 59 की उम्र में पार्टी की कमान संभाली। उसके नए मुख्यमंत्रियों पर नजर डालिए- योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, मोहन चरण मांझी, बिप्लब देब, हिमंत सरमा, मनोहरलाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी, रेखा गुप्ता- इन 12 नेताओं ने जब कुर्सी संभाली तब उनकी औसत उम्र 51 साल थी।

कांग्रेस ने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कुछ युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन यह कर्नाटक में सिद्धारमैया पर ही अटकी हुई है। उल्लेखनीय यह भी है कि संघ स्वयं अपनी सलाह पर अमल करता है। अब तक उसके सरसंघचालकों की अधिकतम उम्र 78 साल ही रही है। हेडगेवार और गोलवलकर का क्रमशः 51 और 67 की उम्र में ही निधन हो गया था। सभी सरसंघचालक युवावस्था में ही शीर्ष तक पहुंचे और भागवत की तरह सबका कार्यकाल लंबा रहा।

हकीकत यह है कि तमाम अफवाहों और कानाफूसियों के बावजूद भाजपा के अंदर किसी ने ऐसे किसी नियम का मुद्दा नहीं उठाया है कि 75 की उम्र रिटायर्ड होने की उम्र है। इसके बारे में कानाफूसी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि को 'मार्गदर्शक मंडल' यानी संन्यास में भेजने के औचित्य के रूप में ही की गई थी। इसी के साथ कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला सरीखे नेता मंत्री बने रहे।

बाद में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी को 75 की उम्र पार करने के बाद भी मथुरा से शायद यह जताने के लिए उम्मीदवार बनाया गया कि पार्टी में 75 की उम्र वाला कोई नियम नहीं लागू है। एकमात्र औपचारिक बयान आनंदीबेन पटेल का है, जिन्होंने 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का यह कारण बताया था कि मैं 75 की हो चुकी हूं। लेकिन यह निश्चित रूप से मोदी के लिए कोई मिसाल नहीं है।

मोदी 2029 का चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ना चाहेंगे। तब उनकी उम्र केवल 79 साल होगी, जितनी आज ट्रम्प की है। बाकियों को उनके फैसले या संकेत का इंतजार करना पड़ेगा, चाहे भाजपा के अंदर 'उम्मीदवार' चुनने की कोई गुप्त 'प्रक्रिया' क्यों न शुरू हो चुकी हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भूखमरी के बीच चांद पर बस्ती बनाने की तैयारी

संजय कुमार

दुनिया भर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास में नई-नई मिसाल कायम की जा रही हैं। इसी का दंभ भरकर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करने या फिर भविष्य में चांद पर बस्ती बसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मगर, क्या वास्तव में विकास का पैमाना यही है? समाज के समग्र उत्थान का तत्त्व विकास की इस धारा में कहां है? यह कैसा विकास है कि एक तरफ विभिन्न देश तकनीक के बूते खुद के ताकतवर एवं साधन संपन्न होने का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी के कारण अपने शरीर की ताकत भी खो रहे हैं।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की 'वैश्विक खाद्य संकट' पर एक हालिया रपट में किए गए खुलासे चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में उनतीस करोड़ से अधिक लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं, जहां उनके लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल है। साफ है कि समाज का सबसे कमजोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, प्राकृतिक आपदा और जबरन विस्थापन जैसी समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। संसाधनों के अभाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की डगर ज्यादा कठिन हो गई है। रपट में सामने आया है कि 2024 में लगातार छठे वर्ष दुनिया में गंभीर खाद्य संकट और बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 53 देशों या क्षेत्रों के 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे थे। यह आंकड़ा वर्ष 2023 के मुकाबले 1.37 करोड़ अधिक है। यानी सुधार के बजाय स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब हो गई है। भुखमरी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें दो देशों के बीच युद्ध और आंतरिक संघर्ष प्रमुख हैं।

इन दो कारणों से ही बीस देशों में करीब 14 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की वजह से हालात और ज्यादा बदतर हो रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर खाद्य सामग्री पहुंचाने पर रोक लगा देने की खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह के प्रयास वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के दम तोड़ देने की ओर इशारा करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से उपजी विकट आर्थिक स्थितियां भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं। रपट में कहा गया है कि इन दोनों कारणों से पंद्रह देशों में 5.94 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है। इसके अलावा, सूखा और बाढ़ ने 18 देशों में 9.6 करोड़ लोगों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। इस पर तुर्रा यह है कि इन लोगों को खाद्य एवं पोषण सहायता के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद में भी भारी गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि वैश्विक मदद और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सांसें धीरे-धीरे उखड़ रही हैं। ऐसे में जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है। 21वीं सदी में भी अगर भुखमरी की समस्या विकराल होती जा रही है, तो यह व्यवस्था के साथ-साथ मानवता के लिए भी खतरे की घंटी है। इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि संकटग्रस्त इलाकों में स्थानीय खाद्य प्रणालियों और पोषण सेवाओं में निवेश पर जोर दिया जाए। समय आ गया है कि विभिन्न देशों की सरकारें जनकल्याण की योजनाओं की व्यापक समीक्षा करें और भुखमरी को दूर करने के लिए उचित एवं प्रभावी उपाय किए जाएं। खाली पेट के सवाल का जवाब खाली हाथों और पीठ फेरकर नहीं दिया जा सकता।

साप्ताहिक शहर सत्ता

फर्जी दूतावास से 300 करोड़ का घोटाला

162 बार विदेश यात्रा, सऊदी के आर्म्स डीलर से सांठगांठ

नई दिल्ली। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन पूछताछ में नोएडा एसटीएफ के सामने रोज नए राज खोल रहा है. पुलिस सोमवार (28 जुलाई 2025) अदालत में हर्षवर्धन जैन की हिरासत की मांग करेगी. पुलिस के अनुसार, जैन लगभग 300 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हो सकता है. यह घोटाला विदेश में लोन दिलाने के नाम पर किया गया.

एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार आरोपी के आवास से ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता है कि उसने हसान अली सैयद के साथ मिलकर विदेशों में बहुत सी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई हैं. अभी तक उसके 25 कंपनियों और बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है. उसने 10 सालों में 162 बार विदेश यात्रा की है. फर्जी दूतावास पर छापेमारी के दौरान, पुलिस को हर्षवर्धन जैन की चर्चित व्यक्ति चन्द्रास्वामी और सऊदी आर्म्स डीलर अदनान खगोशी के साथ तस्वीरें मिली.

चन्द्रास्वामी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में वे जांच के घेरे में आए और 1996 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उनके आश्रम पर छापेमारी में आर्म्स डीलर खशोगी के साथ लेन-देन का भी खुलासा हुआ. चंद्रास्वामी पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए फंड मुहैया कराने का भी आरोप था. यूपी एसटीएफ ने जांच में पाया कि चंद्रास्वामी ने ही हर्षवर्धन जैन को खसोगी और ठग अहसान अली सईद से मिलवाया था. सईद पर आरोप है कि उसने हर्षवर्धन के साथ मिलकर 25 फर्जी कंपनियां खोलीं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया. अहसान अली सईद का जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन बाद में वह तुर्किए का नागरिक बन गया.

घोटाले की जांच कर रही पुलिस

अहसान सईद स्विट्जरलैंड में वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप नामक एक कंपनी चलाता था, जो दूसरी कंपनियों से संपर्क करके उन्हें ब्रोकरेज के बदले कर्ज दिलाने का वादा करती थी. आरोप है कि इस कंपनी ने 2.5 करोड़ पाउंड यानी करीब 300 करोड़ रुपये की ब्रोकरेज वसूली की और स्विट्जरलैंड से भाग गई. उसे 2022 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अब इस बड़े घोटाले में हर्षवर्धन जैन की संलिप्तता की जांच कर रही है. इससे पहले पुलिस को पता चला था कि जैन नेटवर्किंग के लिए फर्जी दूतावास का इस्तेमाल करता था और लोगों को नौकरी का लालच देता था. हर्षवर्धन जैन ने 2005 से 2015 के बीच 162 बार विदेश की यात्रा की. इस दौरान उसने 19 देशों का दौरा किया. हर्षवर्धन सबसे ज्यादा 54 बार यूएई, 22 बार यूके का दौरा किया. इसके अलावा उसने इटली, सेबोर्गो, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, थाइलैंड, पोलैंड, श्रीलंका, तुर्किए, मॉरीशस, फ्रांस, कैमरून और पोलैंड का यात्रा की.

कांगो में आतंकियों ने चर्च पर किया हमला, 21 लोगों की मौत

कांगो। मध्य अफ्रीका के एक देश रिपब्लिक ऑफ कांगो में रविवार (27 जुलाई, 2025) को बड़ा आतंकी हमला हुआ है. इस्लामिक स्टेट (ISIS) के समर्थन वाले विद्रोही समूह अलायड ड्रेमोक्रेटिक फोर्स (ADF) ने पूर्वी कांगो स्थित एक कैथोलिक चर्च परिसर में हमला किया है. इस हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है. इस बात की जानकारी सिविल सोसायटी के एक नेता ने दी है. सिविल सोसायटी के नेता के मुताबिक, आईएसआईएस समर्थित विद्रोही समूह अलायड ड्रेमोक्रेटिक फोर्स (ADF) ने पूर्वी कांगो के कोमांडा स्थित एक कैथोलिक चर्च के परिसर में यह हमला रविवार तड़के करीब 1 बजे किया. इस आतंकवादी हमले में कई स्थानीय घरों को भी नुकसान हुआ है. हमले के दौरान कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया. कोमांडा के सिविल सोसायटी को-ऑर्डिनेटर दियूदोने दूरंथाबो के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "इस आतंकी हमले में 21 से ज्यादा लोगों को चर्च परिसर के अंदर और बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

मालदीव का यू-टर्न, गाने लगा भारत के गुण, चीन तिलमिलाया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दो दिवसीय दौरे से लौट आए हैं. यह यात्रा खास इसलिए रही क्योंकि उन्हें मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था. यह राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद किसी विदेशी नेता की पहली उच्चस्तरीय यात्रा थी. इस दौरे में भारत ने मालदीव के लिए 565 मिलियन डॉलर (करीब 4,800 करोड़ रुपये) की बड़ी क्रेडिट लाइन की घोषणा की, जिसका उपयोग अस्पताल, स्कूल, हाउसिंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े परियोजनाओं में किया जाएगा. इसके साथ ही भारत और मालदीव के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर बातचीत शुरू करने पर भी सहमति बनी. मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार और 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' करार दिया.

मुइज्जू इंडिया आउट का नारा देकर ही सत्ता में आए थे, जिसके बाद भारत को अपनी सेना भी वापस बुलानी पड़ी और अब वो खुद चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील हो और भारत के लोग वहां पहले की तरह ही पर्यटक बनकर जाएं ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रहे. भारत-मालदीव के बीच बढ़ती नजदीकी से चीन की चिंता बढ़ गई है।

थाईलैंड और कंबोडिया सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेता आपसी सीजफायर (सीज़फायर) के लिए जल्द ही मुलाकात करेंगे. दोनों देशों के बीच पिछले तीन दिनों से सीमा पर हिंसक झड़पें जारी हैं, जिनमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1.3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं. राष्ट्रपति ट्रंप इस समय स्कॉटलैंड दौरे पर हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फूमथम वेचायाचाई और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट से अलग-अलग बातचीत की है. ट्रंप ने दोनों को चेतावनी दी कि अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिका उनके साथ व्यापारिक समझौते नहीं करेगा. ट्रंप ने लिखा, "दोनों देश तुरंत शांति चाहते हैं और सुलह के लिए तैयार हैं. दोनों नेता जल्द ही मिलकर सीजफायर की दिशा में काम करेंगे." हालांकि, व्हाइट हाउस या दोनों देशों की दूतावासों ने इस की पुष्टि नहीं की है।

मरे हुए लोग भी बिहार में भर रहे SIR का फॉर्म, उठे सवाल

नई दिल्ली। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और आरजेडी ने आरोप लगाया है कि SIR में अनियमितताएं पाई गई है. याचिकाकर्ता ने कहा, "बीएलओ खुद गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करते पाए गए. मृत लोगों को फार्म भरते हुए दिखाया गया और जिन लोगों ने फार्म नहीं भरे थे, उन्हें यह संदेश दिया गया कि उनके फार्म पूरे हो गए हैं." चुनाव आयोग के इस दावे का विरोध करते हुए कि इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है. याचिकाकर्ताओं ने शनिवार (27 जुलाई 2025) को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अधिकांश फॉर्म बिना दस्तावेजों के जमा किए गए थे. आरजेडी ने आरोप लगाया, "चुनाव आयोग की ओर समय पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना बीएलओ की ओर से बड़े पैमाने पर गणना फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं. कई मतदाताओं ने बताया है कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए हैं, जबकि उन्होंने कभी किसी बीएलओ से मुलाकात नहीं की और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए." ADR ने कहा कि मृत व्यक्तियों के भी फॉर्म जमा किए गए हैं. सुप्रीम को दिए जवाब में आरजेडी ने कहा, "मीडिया रिपोर्टों में ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए गए हैं जहां मतदाताओं ने शिकायत की है कि बीएलओ उनके घर या मोहल्ले में नहीं आए।

जेलेंस्की के नरम पड़े तेवर, पुतिन को सीजफायर का ऑफर

नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार हैं और यह बातचीत अगले सप्ताह आयोजित की जा सकती है. यह बयान उस समय आया है जब रूस-यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों को मानवीय, सैन्य और आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो चुका है. जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के साथ सीजफायर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. अगर ईमानदारी से बातचीत होगी तो यूक्रेन भी गंभीरता से शामिल होगा. इस बयान के बाद दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य देशों की प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी बताया कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के समन्वय पर गंभीरता से कार्य कर रही है.

आयुष्मान भारत के 1.21 लाख करोड़ का बिल बकाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार (25 जुलाई 2025) को संसद में बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत के तहत 9.84 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने प्रताप राव जाधव ने बताया कि देश में आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY) के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं. इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 5.33 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं. उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा का स्थान है। लक्षद्वीप में सबसे कम 36,000 कार्ड जारी किए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने आयुष्मान भारत के तहत बकाया बिलों पर चिंता जताई है, जो अस्पताल की वित्तीय स्थिति के लिए खतरा है. गुजरात में 2021 से 2023 तक के 300 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. यहां केवल 5 फीसदी बिल का ही निपटारा 15 दिनों के भीतर किया गया है.

अजय बसुदेव बोस की ओर से दायर एक आरटीआई के अनुसार केरल में 400 करोड़ रुपये का बकाया है और देश में 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अभी भी बकाया है. आईएमए ने यह भी बताया कि पैकेज दरें बहुत कम हैं और वे उपचार में लगने वाले पैकेज को कवर नहीं करती है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने कहा, "दरें और पैकेज तय करते समय आईएमए को बुलाना चाहिए और हमें समय पर भुगतान करने की प्रकिया सुनिश्चित करनी चाहिए. आईएमए ने सिफारिश की है कि भुगतान को ऑटोमेटिक करें और पारदर्शिता के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग बनाएं.

डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाएं- IMA

आईएमए ने कहा, "डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाएं और 24/7 डिजिटल सहायता प्रदान करें जैसे- व्हाट्सएप, एसएमएस. मान्यता प्राप्त और ग्रामीण अस्पतालों को अधिक भुगतान और जल्दी अप्रूव कर प्रोत्साहित करें." डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि सुधारों के बिना, भारत के सबसे गरीब लोगों को मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का योजना का उद्देश्य खतरे में पड़ जाए.

जडेजा-सुंदर के पराक्रम से ड्रा हुआ चौथा टेस्ट

कप्तान गिल ने भी लगाया शतक, राहुल की जुझारू पारी

लंदन। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया चौथा मैच ड्रॉ रहा। इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का अंतिम मुकाबला 31 जुलाई से ओवल में खेला जाएगा। भारत दूसरे दिन की शुरुआत 0/2 से की, लेकिन कप्तान शुबमन गिल ने 103 रन की बेहतरीन पारी खेली, जो इस श्रृंखला में उनका चौथा टेस्ट शतक था, और उन्होंने KL राहुल (90) के साथ मिलकर 188 रन की साझेदारी की जो टीम को स्थिति से बाहर ले गई। राहुल के आउट होने के बाद, रविंद्र जडेजा (107)* और वॉशिंगटन सुन्दर (100)* ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए एक अटूट साझेदारी निभाई। दोनों ने मैच बचाने में अहम भूमिका निभाई और ड्रॉ सुनिश्चित किया।

पहली पारी में इंग्लैंड ने भारत के 358 रनों के जवाब में 669 रन ठोक दिए। जीरो रन पर दो विकेट लेने के बाद भी इंग्लैंड की टीम 5 सेशन में भारत को ऑलआउट नहीं कर पाई। शुभमन गिल के साथ ही भारत के लिए रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने शतक लगाया। तीसरे विकेट के लिए राहुल और गिल ने 188 रनों की साझेदारी की थी। इन दोनों के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाल लिया। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के पास अभी भी 2-1 की बढ़त है।

भारतीय टीम ने 5वें दिन पहले सेशन में दो विकेट खो दिए। पहले केएल राहुल 90 रन बनाकर आउट हुए। शतक पूरे करते ही शुभमन गिल आउट हो गए। ऋषभ पंत के अनफिट होने की वजह से वॉशिंगटन सुंदर 5वें नंबर पर उतरे। उनके बाद रविंद्र जडेजा आए। इंग्लैंड को जीत की सुगंध आने लगी होगी लेकिन इन दोनों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में भी इंग्लिश गेंदबाज कोई विकेट नहीं ले पाए। रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक लगाया। वॉशिंगटन सुंदर ने पहली बार अपने टेस्ट करियर में शतक ठोका। जब दोनों ही टीमें ड्रॉ के लिए राजी हुईं तो भारत का स्कोर 4 विकेट पर 425 रन था। सुंदर 101 और जडेजा 107 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए 203 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। शुभमन गिल ने 103 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स को दो जबकि बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को 1-1 विकेट मिला।

रद्द हुआ एशिया कप तो पाक को होगा नुकसान

नई दिल्ली। 26 जुलाई को एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया था. जैसे ही शेड्यूल सामने आया तभी से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को आड़े हाथों लिया जा रहा है. यह अब राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता BCCI के पाकिस्तान के साथ खेलने के फैसले की आलोचना कर रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है और लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था. इस बवाल के बीच एक बार फिर एशिया कप को रद्द किए जाने की अटकलों ने तूल पकड़ लिया है.

अगर एशिया कप रद्द होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. चूंकि एशिया कप की मेजबानी पहले भारत करने वाला था, लेकिन एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की बैठक में BCCI ने न्यूट्रल वेन्यू पर टूर्नामेंट का आयोजन करवाने पर हामी भर दी थी. भारतीय फैंस, विपक्ष के दबाव में आकर BCCI एशिया कप को रद्द करने का फैसला लेता है तो जानिए पाकिस्तान को कितने करोड़ों का लॉस हो सकता था.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस साल ICC और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) से से मिलने वाले राजस्व के अपने हिस्से से लगभग 880 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की उम्मीद है. इनमें उसे ICC से 25.9 मिलियन डॉलर यानी करीब 770 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, वहीं PCB को एशिया कप से 116 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है. इसके अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन से उसे 77 लाख पाकिस्तानी रुपयों की कमाई की उम्मीद है.ICC और ACC से मिलने वाली राशि पाकिस्तान क्रिकेट की वित्तीय हालात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में एशिया कप रद्द हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 116 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान तो होता ही, साथ ही इसका असर अन्य ICC इवेंट्स और अन्य कार्यक्रमों पर भी हो सकता था.

मुसीबत में फंसे नितीश करोड़ो रुपये की धांधली का आरोप

नई दिल्ली। नितीश कुमार रेड्डी भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण वह चौथे टेस्ट से पहले बाहर हो गए और भारत लौट आए हैं. यहां उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु स्थित टैलेंट मैनेजमेंट फर्म स्क्वायर द वन ने नितीश के खिलाफ कानूनी मामला दायर किया है. इसमें भारतीय क्रिकेटर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया नहीं चुकाया है. यह मामला कोर्ट में हैं और इसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 28 जुलाई को होगी. न्यूज18 क्रिकेटनेक्स्ट ने स्क्वायर द वन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिव धवन से संपर्क किया. उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विवरण की पुष्टि की, लेकिन मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से परहेज किया।

क्या 2000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर लगेगा जीएसटी?

नई दिल्ली। देश में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे यूपीआई ट्रांजेक्शन, सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं. हाल ही में यूपीआई पर जीएसटी लगाए जाने की खबरों के बीच, वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं किया गया है. मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि दो हजार रुपये के ऊपर ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की सिफारिश नहीं की गई है.

दो हजार रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर जीएसटी के बारे में सरकार के विचार पूछे जाने के एक सवाल का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर जीएसटी की दरें और छूट पर फैसला किया जाता है. यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें राज्य और केन्द्र दोनों के सदस्य शामिल हैं.गौरतलब है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जीएसटी का मामला उस वक्त सामने आया, जब कर्नाटक में यूपीआई लेनदेन के डेटा के आधार पर व्यापारियों को करीब 6000 जीएसटी नोटिस जारी किया गया है. कर्नाटक में व्यापारियों के संगठन ने जीएसटी लेनदेन के डेटा को आधार बनाकर भेजे गए जीएसटी नोटिस के खिलाफ सड़क पर उतरकर हड़ताल करने की धमकी दी है. जबकि आयकर अधिकारियों ने इसे कानून के मुताबिक सही कदम बताया है. कॉमर्शियल टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर मीरा सुरेश पंडित ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि जब सेवा क्षेत्र में ट्रांजेक्शन लिमिट 20 लाखकर और वस्तुओं के लिए सीमा 40 लाख को पार कर जाती है, उस स्थिति में जीएसटी एक्ट के तहत अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है।

आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को लग सकता है झटका

नई दिल्ली। केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस वक्त आठवें वेतन आयोग का इंतजार है. इस साल जनवरी में ही आयोग के गठन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हो पाया है. इस बीच, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आयी है, जिसे जानकार केन्द्र सरकार के करीब 33 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है. दरअसल, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि सातवें वेतन आयोग की तुलना में आठवें वेतन आयोग का फिटमैंट फैक्टर कम रह सकता है. इसमें कहा गया है कि फिटमैंट फैक्टर करीब 1.8 रह सकता है, जिसके चलते वेतन में सिर्फ तेरह प्रतिशत तक का ही इजाफा देखने को मिल सकता है.फिटमैंट फैक्टर किसी भी स्टाफ के बैसिक वेतन के आधार पर उसके नए बैसिक वेतन निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है. यानी, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सातवें वेतन आयोग के लिए फिटमैंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. उस स्थिति में अगर किसी का मूल न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये था तो यह बढ़कर 51,400 रुपये हो गया.

भारत-यूके डील से कृषि निर्यात में 50% की छलांग

नई दिल्ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। यह समझौता दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.इस साझेदारी के साथ यूके को भारत के 99 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त हो गया है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100 प्रतिशत है. वहीं,इसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण और खिलौने जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र, साथ ही इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्र शामिल हैं.

केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूके को निर्यात किए जाने वाले भारतीय समुद्री उत्पादों, वस्त्र, चमड़ा और प्रोसेस्ड फूड पर शुल्क शून्य कर दिया गया है, जो कि पहले 70 प्रतिशत था.भारत वैश्विक स्तर पर 14.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोसेस्ड फूड उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि यूके 50.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात करता है, लेकिन भारतीय उत्पादों का योगदान केवल 309.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. अगले 3 वर्षों में कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों के निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद के साथ, भारत यूके सीईटीए का भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड फूड क्षेत्र पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.यह समझौता भारतीय कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूके के बाजार लगभग सभी भारतीय कृषि निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त हो गए हैं.भारत-यूके सीईटीए भारतीय किसानों को यूके के बाजार में इन उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा. यह समझौता वस्तुओं से आगे बढ़कर सेवाओं पर भी केंद्रित है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख ताकत है।

सरकार के अनुसार, भारत ने 2023 में यूके को 19.8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सेवाओं का निर्यात किया और सीईटीए ने इसे और बढ़ाने का वादा किया हैय यूके द्वारा पहली बार, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और शिक्षा क्षेत्र के पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाया जा रहा है. क और बड़ी सफलता दोहरी योगदान संधि (डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन) है, जो दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान की आवश्यकता को समाप्त कर भारतीय फर्मों और श्रमिकों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत कराएगी.दोनों देशों के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

एक्शन में ED, अनिल अंबानी की कंपनियों पर छापेमारी

नई दिल्ली। रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ मुंबई में केन्द्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही. जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर डिवाइसेज जब्त किए. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने तीन हजार करोड़ रुपये के बैंक लोन फर्जीवाड़े से जुड़े मनीलांड्रिंग मामले में 24 जुलाई को एक्शन लेते हुए छापेमारी शुरू की थी. इसके साथ ही, कुछ कंपनियों की तरफ से करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगाए गए हैं. पीटीआई के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनीलांड्रिंग के तहत गुरुवार को ईडी ने छापेमारी शुरू की थी और मुंबई में करीब 35 से ज्यादा परिसरों में कुछ ठिकानों पर शनिवार को भी छापेमारी की।

साप्ताहिक शहर सत्ता

कांग्रेस ने की आर्थिक नाकेबंदी व विरोध प्रदर्शन

पीसीसी चीफ और भाजपा अध्यक्ष में जुबानी जंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई और तमनार में जंगलों की कटाई के खिलाफ बस्तर में भी कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान रायपुर जगदलपुर मार्ग पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे. बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल व कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस के आंदोलन की निंदा की है.

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा "ईडी की कार्रवाई पर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में और उनके चहेते उद्योगपति को जल जंगल जमीन व खनिज संसाधन सौंपने के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी के तहत चक्काजाम किया गया. बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सफल रही. डबल इंजन की सरकार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विरोधी दल के नेताओं को डराने और जेल भेजने का काम कर रही है. जिसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया."पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा "ईडी ने पप्पू बंसल पर गैर जमानती धारा लगाने के बावजूद वे खुलेआम कैसे घूम रहे हैं. उनको किसने संरक्षण दिया है. एक तरफ सरकार के खिलाफ सेफ जोन व विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई यह नहीं चलेगी. 15 सालों में काफी भ्रष्टाचार हुआ है. इस सरकार में 32 हजार में जग, 100 रुपये का चप्पल 1300 में बिक रहा है. 1 लाख का टीवी 10 लाख में बिक रहा है. 20 हजार में चम्मच बिक रहा है. क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है. इसका जांच कौन करेगा. यह बड़ा सवाल है." चैतन्य बघेल के कांग्रेसी नेता नहीं होने के भाजपा के आरोप पर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा "केवल चैतन्य बघेल का सवाल नहीं है. सवाल इस लोकतंत्र की हत्या का है. जो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है. कवासी लखमा को जेल भेजा गया. देवेंद्र यादव को जेल भेजा गया. यूथ कांग्रेस के नेताओ को जेल भेजा गया. भूपेश बघेल के घर में लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है. क्या भाजपा के नेता दूसरे हरिश्चंद्र हैं।

किरण देव का पलटवार

कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला और गौठान घोटाला किया. अब जब केंद्र की स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच कर रही है. संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है. उसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है और आर्थिक नाकेबंदी कर रही है. देव ने कहा "पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे कौन से कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिनके लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ को अस्त व्यस्त करने में लग गई है. चैतन्य बघेल केवल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ही है, कोई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है. कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी घोटाले में अंदर गए हैं. उस समय क्यों आर्थिक नाकेबंदी नहीं की गई और इस समय आर्थिक नाकेबंदी की गई. इसकी निंदा करते हैं."

कांग्रेस के बंद पर डिप्टी सीएम की चुटकी

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की ओर से किए गए आर्थिक नाकेबंदी पर तंज कसा. अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन और बंद पूरी तरफ से सुपर फ्लाप रहा. बंद का समर्थन न तो कारोबारियों ने किया न आम जनता ने. डिप्टी सीएम ने कहा कि बंद पूरी तरह से असफल रहा. अरुण साव ने कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल दोनों को बता दिया कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकती है.

चैतन्य बघेल से मिले सचिन पायलट बोले-बीजेपी की धमकी से नहीं डरेगी कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने शनिवार को रायपुर प्रवास के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। वहीं इसी जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि चैतन्य ने मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात कही है। आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार विपक्ष को डराने और दबाने के लिए कंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं पर भाजपा चाहे जो भी कर लें, हमारा कांग्रेस परिवार एक कदम पीछे नहीं हटेगा। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों को दबाने के लिए कर रही है। दस साल में किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी ने कोई भी जांच या कार्रवाई नहीं की है। पायलट ने आरोप लगाया कि मैंने आज चैतन्य बघेल से मुलाकात की। हम बार-बार कह रहे हैं कि भाजपा और उसकी केंद्र और राज्य सरकारें लगातार अपने विरोधियों को धमकाने और डराने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं और अब पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से साबित होता है कि केंद्र और राज्य की जाँच एजेंसियाँ भाजपा के राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं।

'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा'

उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सच्चाई सामने आएगी। भूपेश बघेल ने भी कहा है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन यह कार्रवाई दर्शाती है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग आदि का इस्तेमाल भाजपा विरोधियों, खासकर कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी विधायक कवासी लखमा और देवेंद्र यादव जैसे हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

हरेली पर छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर राजनीतिक टकराव

रायपुर। हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर और राज्यगीत को लेकर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ की पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों को कमजोर कर रही है। भूपेश बघेल का आरोप है कि सरकारी आयोजनों में अब राज्यगीत नहीं गाया जा रहा और महतारी का मोनो भी विज्ञापनों और पोस्टरों से हटा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आए थे तब मंच पर महतारी की तस्वीर थी, लेकिन इस बार हरेली पर्व के पोस्टरों में यह नहीं दिखाई दी। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को राज्य की अस्मिता से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल को नकली छत्तीसगढ़िया कहना ही सही है क्योंकि उनके कार्यकाल में शराब घोटाले से लेकर छात्राओं के विरोध प्रदर्शन जैसे मामले सामने आए और छत्तीसगढ़ की छवि खराब हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही राज्य का मान और गौरव स्थापित किया है। हरेली पर्व के बाद महतारी के प्रतीक और राज्यगीत को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में और गहराने की संभावना है।

दिल्ली में 'पप्पू' और छत्तीसगढ़ में बिट्टू यही कांग्रेस की राजनीतिः मिश्रा

रायपुर। बीजेपी के रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने ईडी की कार्रवाई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में की गई कांग्रेस की आर्थिक नाकाबंदी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में 'पप्पू' और छत्तीसगढ़ में 'बिट्टू', क्या यही कांग्रेस की राजनीति बची है? इतना ही नहीं मिश्रा यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दैनिक मजदूरी पर मजदूरों को लाकर आर्थिक नाकाबंदी करवाई थी, लेकिन कुछ मजदूरों को उस दिन का पेमेंट नहीं मिला और वे लोग बाद में हल्ला मचा रहे थे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पायलट को कम-से-कम उन मजदूरों का पेमेंट तो करवा देना चाहिये। भाजपा विधायक मिश्रा ने यह भी जानना चाहा है कि सचिन छत्तीसगढ़ आकर क्या यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद में ही सिमटकर रह गई है? कांग्रेस के वैचारिक दीवालिएपन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि 1,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के मामले में गिरफ्तार भूपेश बघेल के उस बेटे के बचाव में किया गया जो कांग्रेस का पदाधिकारी तक नहीं है!

उपराष्ट्रपति पद को लेकर बैज ने लिखा पीएम को पत्र, गरमाई सियासत

रायपुर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा देने के बाद अब नए उपराष्ट्रपति को लेकर राजनीतिक दांव पेंच तेज हो गई है. इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक नई सियासी चिंगारी फेंक लगा दी है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीके नाम एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है. लिहाजा, इस पत्र पर सियासत तेज हो गई है. दीपक बैज के इस पत्र के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं होगा? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के निर्णय भी प्रदेश स्तर पर ही लिए जाएंगे? दीपक बैज के इस पत्र से छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं में उम्मीद जगेगी? क्या कांग्रेस के उपराष्ट्रपति चुनाव में खुद को हारा हुआ मान रही है?

दरअसल, बैज ने जो पत्र लिखा है. उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को तीनों कार्यकालों में सिर्फ राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व मिला, जो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है. छत्तीसगढ़ भाजपा में कई अनुभवी और योग्य नेता हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त हैं. इनमें रमेश बैस, डॉक्टर रमन सिंह, धरमलाल कौशिक हैं. वर्ष 2000 से अब तक छत्तीसगढ़ ने हर आम चुनाव में भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है. वर्ष 2014 में भाजपा ने राज्य की 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीतीं, 2019 में 9 और हालिया 2024 के आम चुनाव में फिर से 10 सीटों पर जीत दर्ज की. लिहाजा, अब छत्तीसगढ़ का ये सम्मान मिलना चाहिए.

टीएस सिंहदेव ने बताया निजी राय

दीपक बैज के इस पत्र पर कांग्रेस के नेताओं ने खुद ही किनारा करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये उनकी राय है. हालांकि, उन्होंने आगे कहा उनकी मंशा छत्तीसगढ़ को तवज्जो देने की मांग करना है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति क्यों नहीं बनना चाहिए. अगर बनते हैं तो अच्छी बात है.

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए निशाना साधा है. छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज ने पत्र लिखकर यह साबित कर दिया है कि वो भी मानते हैं कि देश का भविष्य बीजेपी के हाथों में ही सुरक्षित है. साथ ही उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि उपराष्ट्रपति के लिए कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों के पास कोई योग्य चेहरा नहीं है. इसलिए ही वे बीजेपी नेताओं के नाम सुझा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की कथनी और मंशा में अंतर होता है. अगर वे ऐसा करके चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं में भेद उत्पन्न होगा, तो वे पूरी तरह से गलत हैं.

टीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर छत्तीसगढ़

अब तक 4106 ग्राम पंचायतें हुईं टीबी मुक्त घोषित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी और सुनियोजित प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी व्यापक कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के दिशानिर्देशन में 7 दिसंबर 2024 को "निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़ – 100 दिवसीय अभियान" की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य था – टीबी के विरुद्ध जमीनी स्तर पर निर्णायक लड़ाई छेड़ना। अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में घर-घर जाकर उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करते हुए आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जांच कराई गई। इस अभियान के तहत 36 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, 4.5 लाख से अधिक एक्स-रे जांचें की गईं और 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच अत्याधुनिक 'नॉट मशीन' से की गई। यह व्यापक परीक्षण प्रक्रिया टीबी की शीघ्र पहचान और त्वरित उपचार के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई।

इस अभियान की सफलता में जनभागीदारी की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। स्वयं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मरीजों को गोद लेकर 'निक्षय मित्र' के रूप में पोषण आहार उपलब्ध कराने की पहल की। अब तक 15,000 से अधिक नए निक्षय मित्रों ने पंजीकरण कर 34,000 से अधिक मरीजों को पोषण सहायता प्रदान की है। राज्य के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, महिलाएं, युवा वर्ग, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक इस अभियान में सक्रिय रूप से सहभागी बने हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं – जैसे कि जेलों में बंद बंदी, वृद्धाश्रमों के बुजुर्ग, छात्रावासों में रह रहे छात्र तथा फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिक। इनके लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर जांच और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

इन समर्पित प्रयासों और सामूहिक भागीदारी का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राज्य को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अब तक राज्य की 4106 ग्राम पंचायतों को "टीबी मुक्त" घोषित किया जा चुका है — जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब शासन की प्रतिबद्धता और जनसहयोग एक साथ मिलते हैं, तब बदलाव सिर्फ लक्ष्य नहीं, उपलब्धि बन जाते हैं – और छत्तीसगढ़ इसका जीवंत उदाहरण बनने जा रहा है।

टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान

जल स्रोत में क्लोरीनेशन से ग्रामीणों को मिला स्वच्छ जल का तोहफ़ा

रायपुर। जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम राँपा के निवासियों के लिए अब पीने का पानी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और स्वच्छ हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम में स्थापित हैंडपंप के जल स्रोत में क्लोरीनेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं को प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया, जिससे अब ग्रामीणों को संक्रमण मुक्त एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल मिल रहा है। क्लोरीनेशन की यह पहल ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा और कारगर कदम है, जिससे ग्रामीणों को जलजनित बीमारियों से बचाव में सीधा लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी रहती थी, विशेषकर गर्मियों और बरसात के मौसम में जब जल स्रोतों में प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समय रहते इस पहल को अमल में लाना अत्यंत सराहनीय है। विभाग द्वारा नियमित निगरानी, पानी के सैंपल परीक्षण और आवश्यकतानुसार क्लोरीन का उपयोग कर जल स्रोतों को शुद्ध बनाया गया है, जिससे न केवल पेयजल की गुणवत्ता में सुधार आया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

भारत-यूके एफटीए से किसानों, बुनकरों और युवाओं के लिए खुलेगा वैश्विक बाज़ार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत की विकास यात्रा का नया अध्याय बताया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह समझौता न केवल भारत के आर्थिक क्षितिज को विस्तार देगा, बल्कि विशेष रूप से ऐसे राज्य जो कृषि, शिल्प, लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित हैं – जैसे छत्तीसगढ़ – उन्हें वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगा। ख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत-यूके एफटीए से भारत के 99% निर्यात उत्पादों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे किसानों, एमएसएमई, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और पारंपरिक उत्पादों को सीधे लाभ मिलेगा। इस समझौते से अनुमानित $23 अरब डॉलर के नए व्यापार अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ जैसे कृषि और श्रम प्रधान राज्यों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता छत्तीसगढ़ के लिए कृषि को बल, उद्योग को संबल और युवाओं को नए रोजगार के अवसर देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, और निर्यात सहायता केंद्रों की स्थापना पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोटिशः धन्यवाद देते हुए कहा कि यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व का कमाल है।

जल पहुंचाना ही नहीं, जल बचाना भी हो प्राथमिकता : साव

- **पीएचई अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के समापन सत्र में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री**

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव विभागीय अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के समापन सत्र में शामिल हुए। जल जीवन मिशन के तहत निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विभागीय सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता श्री टी.डी. सांडिल्य भी समापन सत्र में शामिल हुए।

एसपीएम-निवास और यूनिसेफ द्वारा दो बैचों में आयोजित प्रशिक्षण में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक पहले बैच के प्रशिक्षुओं को ग्रामीण जलापूर्ति के संस्थागत एवं सामुदायिक पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। वहीं 24 जुलाई से 26 जुलाई तक दूसरे बैच में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के तकनीकी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने तथा क्षेत्रीय अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स को जल संरचना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में दक्ष बनाने के लिए इस सघन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रशिक्षण के समापन सत्र में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पर जोर देते हुए अपने संबोधन में कहा कि हर घर तक जल पहुँचाने के लक्ष्य के साथ हमें जल बचाने की जिम्मेदारी को भी प्राथमिकता देना होगा।

मुख्यमंत्री की पहल पर जशपुर में आर्चरी अकादमी की स्थापना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर जशपुर जिले के पंड्रापाठ में राज्य का अत्याधुनिक तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो ग्रामीण युवाओं की खेल प्रतिभा को सशक्त मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खेल, शिक्षा और ग्रामीण विकास को एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ जोड़कर समग्र उन्नति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जशपुर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र पंड्रापाठ (तहसील सन्ना, विकासखंड बगीचा) में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बहु-उद्देशीय परिसर की स्थापना की जा रही है, जो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त मंच प्रदान करेगा। एनटीपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 20.53 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। परिसर में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, लघु पुस्तकालय, प्राथमिक चिकित्सा इकाई, कौशल विकास केंद्र, जैविक खेती हेतु छायादार नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। परिसर में एक औषधीय उद्यान भी विकसित किया जाएगा।

रायपुर और आस-पास का एरिया, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में होगा विकसित

स्टेट कैपिटल रीजन: छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन

रायपुर। राजधानी रायपुर और उसके आस-पास का एरिया, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ ईंजन बनेगा। विधानसभा में इस संबंध में विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन' ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर के क्षेत्र कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित होगा।

भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के केन्द्र में स्थित होने के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल पर स्टेट कैपिटल रीजन में योजनाबद्ध और शहरी विकास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे राजधानी और आसपास के शहरों का प्लान्ड डेव्हलपमेंट होगा। साथ ही शहरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी। स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल शहरों में वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की आबादी रहने का अनुमान है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को कम करने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि के अनुरूप होगा।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव, राज्य शासन द्वारा नामित सदस्यों में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार विधायक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निर्वाचित सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसके सदस्य संयोजक होंगे।

यह प्राधिकरण भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2024-25 के बजट में स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की स्थापना के लिए सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

चप्पल घिस गई, पर हौसले नहीं

छत्तीसगढ़ से मुंबई तक : बॉलीवुड की ओर बढ़ते कदम

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

शहरसत्ता/रायपुर। सपने छोटे शहरों में पलते हैं, लेकिन उड़ान उन्हें मुंबई की भीड़ में ले जाती है, जहां हर कोना एक कहानी है, हर चेहरा एक किरदार, और हर संघर्ष एक स्क्रिप्ट। यह वो शहर है जो नींद छीन लेता है, लेकिन सपनों को ज़िंदा रखता है। ऑडिशन की लंबी कतारें, जेब में किराया नहीं, पर आंखों में कैमरे की चमक होती है। कोई स्टेशन पर रोता है, कोई स्टूडियो में मुस्कुराता है। जहां 'ना' हज़ार बार सुनने के बाद एक 'हां' सारा खेल बदल देती है। यही मायानगरी है,जो गुमनाम चेहरों को सितारा बना देती है। छत्तीसगढ़ की माटी से उठे वो सपने, जिनमें मुंबई की रौशनी बसती है। ये कहानी सिर्फ कलाकारों की नहीं, बल्कि उस ज़िद, उस उम्मीद और उस हौसले की है, जो हजार किलोमीटर दूर मायानगरी की ओर चल पड़े, एक पहचान बनाने।

हर्षवर्धन पटनायकः स्टेज से स्क्रीन तक

भिलाई के हर्षवर्धन पटनायक उर्फ 'बन्नी' ने स्कूल से थिएटर की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में खूब नाम कमाया। जब लगा कि अब समय है मुंबई जाने का, तो पता चला,लोग छत्तीसगढ़ के नाम तक से अनजान हैं। "दंतेला" फिल्म का ट्रेलर दिखाकर उन्होंने खुद को साबित किया। बन्नी मानते हैं कि पहचान पाना आसान नहीं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। भाषा या लुक्स पर कभी ठोकर नहीं मिली, लेकिन बैकग्राउंड के कारण अवसर जरूर छूटे। छत्तीसगढ़ी कलाकार अभी भी मुंबई की रफ्तार से दो कदम पीछे हैं, पर धीरे-धीरे फासला कम हो रहा है।

सोनल अग्रवाल: हौसले की उड़ान

इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद सोनल अग्रवाल ने 2020 में मुंबई में कदम रखा। शुरुआत में इंडस्ट्री की ABCD तक नहीं पता थी, लेकिन पूरन किरी जैसे दोस्तों का सहारा मिला। रीजनल बैकग्राउंड के कारण कई बार रोल से बाहर कर दिया गया,वो बताती हैं। 'गुड न्यूज़' जैसी फिल्म में काम किया, पर स्क्रीन टाइम कम होने से पहचान नहीं मिली। कास्टिंग काउच का अनुभव भी रहा, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। अब वो 'भाग्यलक्ष्मी', 'धर्मपत्नी' और तमाम ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं, और मुंबई में एक छत्तीसगढ़ी पहचान गढ़ रही हैं।

अमर तिवारीः इंडस्ट्री की सच्चाई

मुंबई जाना 20-22 की उम्र से चाहता था, लेकिन पहुंचा 26 में। भिलाई निवासी अमर तिवारी का सपना था बड़े पर्दे पर खुद को देखना। शुरुआत आसान नहीं थी,न रहना, न खाना तय था। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को लोग भोजपुरी समझते हैं,यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा रही। अमर बताते हैं कि नेटवर्किंग मुश्किल है, ऑनलाइन ऑडिशन तो होते हैं, लेकिन हजारों में से खुद को पहचान दिलाना बड़ी जद्दोजहद है। "मुंबई में धर्म-जाति नहीं, आपकी कला और प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है।" कास्टिंग काउच पर वे कहते हैं, "लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है।"

प्रतीकः सॉफ्टवेयर से सिनेमा तक

प्रतीक ने आईटी से फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। ऑडिशन, नेटवर्किंग, और "भयंकर मित्रा" जैसी टिप्पणियों को पार कर वे आज टीवी और फिल्मों का जाना-पहचाना चेहरा हैं। 'ना आना इस देश लाडो', 'CID', 'सावधान इंडिया' में नजर आ चुके प्रतीक का मानना है, काम ही आपकी पहचान है।उनका लक्ष्य अब है, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना। ये सिर्फ चेहरे नहीं, छत्तीसगढ़ की माटी के वो दीपक हैं जो मुंबई की गलियों में रोशनी कर रहे हैं। 'छॉलीवुड' अब बॉलीवुड से आँख मिलाने की ताक़त रखता है। और यही आवाज़ हम सबकी है जो कहती है- "हम भी आ सकते हैं... स्क्रीन के उस पार।

लोकल टैलेंट के हिस्से समझौता

छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर बॉलीवुड फिल्मों और वेब सिरीज की शूटिंग तो हो रही है, लेकिन यहां के कलाकारों को मुंबई की अपेक्षा आधे से भी कम पर डे में काम कराया जा रहा है। पैसे बचाने के लिए नॉन एक्टर को कास्ट कर रही हैं। छत्तीसगढ़ी कलाकारों को सिर्फ 'भरपाई' का जरिया बना रही हैं। जो कलाकार सिर्फ कलाकारी करके जिंदा हैं उनके हिस्से सिर्फ समझौता आ रहा है।

जिसे किया रिजेक्ट वही बना स्टार

कास्टिंग डायरेक्टर अमरीश शर्मा

मुंबई सपनों का शहर है। यहाँ कोई कैमरे के सामने खड़ा होता है, तो कोई कैमरे के पीछे। अमरीश शर्मा ने जब मायानगरी में क़दम रखा, तो सपना था एक एक्टर बनने का। शुरुआत तो हुई लेकिन तक़दीर को कुछ और मंजूर था। UTV प्रोडक्शन से कास्टिंग की दुनिया में क़दम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी से खास बातचीत

कास्टिंग का असली पैमाना – उम्र और चेहरा

एक्टर के लिए सबसे पहले उसका लुक और उम्र देखी जाती है। उसके बाद ही तय होता है कि वह किस किरदार के लिए फिट बैठेगा।

स्टारकास्ट की जरूरत के हिसाब से होती है कास्टिंग

आज के दौर में जिस रोल में जैसी ज़रूरत होती है, वैसे ही कलाकार को चुना जाता है। यदि नया चेहरा चाहिए, तो स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है, और उसमें फिट बैठने पर ही मौका मिलता है।

रिजेक्ट हुआ और बन गया स्टार

वो बताते हैं कि कई बार जिन कलाकारों को रिजेक्ट किया गया, वही बाद में स्टार बन गए। ये इस इंडस्ट्री की विडंबना है और साथ ही खूबसूरती भी।

नेपोटिज़्म और फेवरिज़्म पर बेबाक राय

फिल्मों में नेपो और फेवरिज़्म ज़रूर चलता है, लेकिन टीवी में नहीं। टीवी की दुनिया में अभिनेता फ़िल्टर होकर आते हैं – वहाँ टैलेंट ही चलता है।

कलाकारों में सबसे ज़रूरी है लुक, फिर टैलेंट और फिर एटीट्यूड

अमरीश मानते हैं कि न्यूकमर्स को सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए – लुक ही पहला टिकट है, फिर टैलेंट और अंत में व्यवहार।

कास्टिंग काउच – एक कड़वी सच्चाई

कास्टिंग काउच होता है। लेकिन इस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों पीड़ित हैं। ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करता – अगर काम मिल गया तो कोई नहीं बोलता, नहीं मिला तो आवाज़ उठती है। यानी 'गिव एंड टेक' का सिस्टम

बीजापुर में पर्यटन के छुपे हुए रत्न

अनछुए पर्यटन स्थलों की रोमांचक दुनिया

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो अभी तक आम पर्यटकों की नजरों से छुपे हुए हैं, लेकिन अपनी मौलिकता, शांति और रोमांचकारी ट्रैकिंग अनुभवों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सुनहरी रेत से सजी नदियाँ, ऊंचे जलप्रपात, पत्थरों की अद्भुत कलाकृतियाँ और घने जंगलों की रहस्यमयी दुनिया—ये सभी मिलकर बीजापुर को साहसिक यात्रियों के लिए एक अनमोल गंतव्य बनाते हैं। हम आपको बीजापुर और आसपास के कुछ ऐसे अनछुए पर्यटन स्थलों से रूबरू करवा रहे हैं, जो हर प्रकृति प्रेमी, रोमांचक ट्रैकर और सांस्कृतिक जिज्ञासु के लिए अवश्य घूमने योग्य हैं।

मट्टी मरका

यह स्पॉट बीजापुर जिले के भोपालपट्नम ब्लॉक में है। भोपालपट्नम से लगभग 20 किमी दूर मट्टीमरका गांव में इंद्रावती नदी किनारे दूर तक बिछी सुनहरी रेत और पत्थरों के बीच से कल-कल बहती इंद्रावती नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है। नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए बहती है। मट्टी मरका को बीजापुर जिले का गोवा भी कहा

नीलम सरई जल प्रपात

बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में स्थित नीलम सरई जलधारा हाल ही के कुछ साल पहले सुर्खियों में आया है। स्थानीय युवाओं की टीम ने इस नीलम सरई जल प्रपात को लोगों के सामने लाया। उसूर के सोढ़ी पारा से लगभग 7 किमी दूर तीन पहाड़ियों की चढ़ाई को पार कर यहां पहुंचा जा सकता है। नीलम सरई जलप्रपात तक का सफर ट्रैकिंग के लिए ही माना जाता है। बस्तर की हसीन वादियों के बीच ट्रैकिंग करने वालों के लिए यहां का सफर रोमांच भरा होता है।

नंबी जल प्रपात

बीजापुर जिले के उसूर ग्राम से 8 किमी पूर्व की ओर नड़पल्ली ग्राम को पार करने के बाद नंबी ग्राम आता है। इस गांव से तीन किमी जंगल की ओर दक्षिण दिशा में पहाड़ पर बहुत ही ऊंचा जलप्रपात है। इसे नीचे से देखने पर एक पतली जलधारा बहने के समान दिखाई देती है। इसलिए इसे नंबी जलधारा कहते हैं। लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस जलधारा को देखकर यह कहा जाता है कि यह बस्तर की सबसे ऊंची जलधारा है।

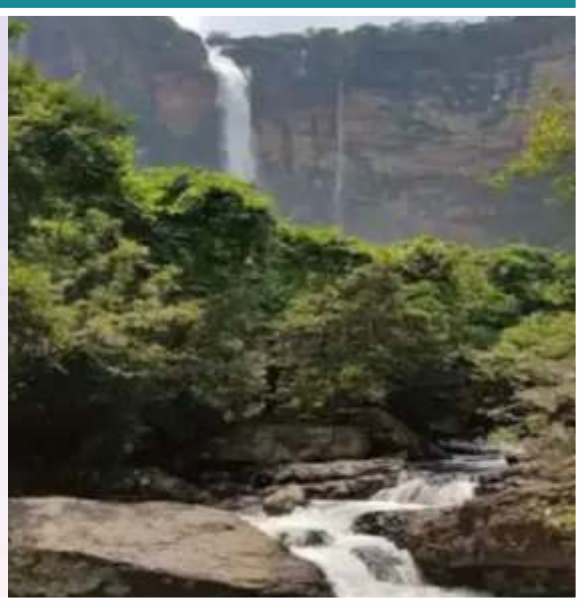

पत्थरों का परिवार दोबे

नीलम सरई से मात्र तीन किमी की दूरी पर एक बेहद शानदार पर्यटन स्थल दोबे स्थित है। दोबे को पत्थरों का परिवार या फिर पत्थरों का गांव भी कहा जाता है। यहां चारों तरफ पत्थरों से बनी हुई अद्भुत कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। बड़े-बड़े पत्थरों से बनी हुई कलाकृतियां किसी किले के समान लगती है। अमूमन शिकार के समय ग्रामीण यहां पहुंचते हैं। चट्टानों की खोह रात गुजारने के लिए बेहद सुकून दायक जगह मानी जाती है। सालभर पहले इसी इलाके की खोज स्थानीय युवाओं ने की थी। ये जगह भी ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए खूबसूरत है।

लंका पल्ली जल प्रपात

बीजापुर जिला मुख्यालय से 33 किमी दूर दक्षिण दिशा की ओर आवापल्ली गांव है। यहां से पश्चिम दिशा में लगभग 15 किमी पर लंकापल्ली गांव बसा हुआ है। जो यहां साल के 12 महीने निरंतर बहने वाले जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की गोद में शांत एवं स्वच्छंद रूप से अविरल बहते इस प्रपात को लोग गोंडी बोली में बोक्ता बोलते हैं। नाइट कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए यह एक शानदार जगह है।

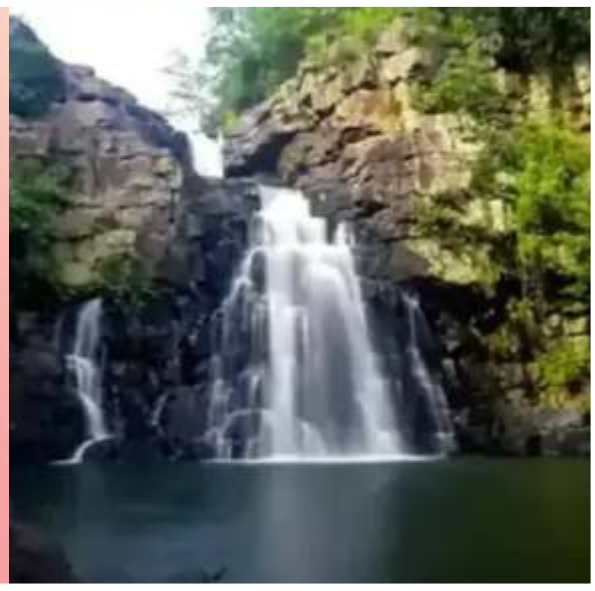

साप्ताहिक शहर सत्ता

“जनता की आवाज़ सरकार तक”

न जांच, न आंच

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में **“शहर सत्ता”** लगातार आम लोगों से जुड़े मुद्दों और भ्रष्टाचार के असर को उजागर करता रहा है। हमारा प्रयास है कि सत्ता और प्रशासन को उनके कामकाज का आईना दिखाएं, क्योंकि कार्रवाई करना उनका दायित्व है। दुर्भाग्य यह है कि कई गंभीर खबरों पर सरकार की सुस्ती और देरी का खामियाजा आमजन को ही भुगतना पड़ता है।

पिछले अंकों में हमने भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की थीं। इन खबरों पर अब तक ठोस कदम न उठने के कारण, हम एक बार फिर इन खबरों का कोलाज प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदार तंत्र को याद दिलाया जा सके कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली जिम्मेदारी है।

10 March to 16 March 2025

24 March to 30 March 2025

14 April to 20 April 2025

बरसात में डूब गया सिस्टम!

ये स्मार्ट सिटी है या पानी सिटी

ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल है... हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी भी कहते हैं... लेकिन, जैसे ही बारिश होती है हमारा शहर स्मार्ट सिटी की जगह पानी सिटी हो जाता है। शहर में हर बार नगर-निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड मिलकर शहर में डुबान जैसी स्थिति से बचाव के लिए नए-नए प्रयोग करती है, बावजूद इसके बारिश हर बार इनके प्रयोग की पोल खुल जाती है।

घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी नदियां
12 साल में पहली बार रायपुर में ऐसी बारिश

शहर के डीडीनगर, समता कॉलोनी, कुशालपुर, रायपुरा विप्रनगर, प्रोफेसर कॉलोनी, भाठागांव, गुढ़ियारी, मोवा जैसे ईलाकों की कई कॉलोनी एक ही बारिश से डुब जाती है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रायपुर में शनिवार को 24 घंटे में 134 मिमी पानी गिरा है। विभाग के अनुसार, रायपुर में करीब 12 साल बाद एक दिन में ऐसी बरसात हुई है। रायपुर में कई निचली बस्तियां और डूबान क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में पानी भर गया है। कुशालपुर इलाके में जलभराव की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घरों में फंसे रहे। जब पानी लोगों के घरों में घुसने लगा तो जरूरी समान लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकले। गुढ़ियारी अंडरब्रिज में पानी भरने की वजह से कई घंटों तक आवाजाही रुकी रही। रायपुर समेत प्रदेशभर में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

प्रोफेसर कॉलोनी में भारी बारिश

प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव हो गया। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर यहीं दिखाई दिया। नालों से निकलकर गंदा पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुस गया। भारी बारिश के कारण कई घरों में घुटने तक पानी भर गया। बारिश थमने के बाद कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जिस कारण से काफी देर तक वहां आवाजाही बंद रही। अमलीडीह और प्रोफेसर कॉलोनी के बाजार चौक, अलमारी कारखाना समेत कई इलाकों में दोपहर के बाद ही सड़कें जलमग्न हो गईं।

निगम के दावों की खुली पोल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश के कारण लोगों के हाल बेहाल हैं। वहीं, दूसरी तरफ नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। बारिश से पहले तैयारियां पुख्ता होने का दावा करने वाली नगर निगम की टीम के सभी दावों की पोल शनिवार को हुई भारी बारिश ने खोल दी। नगर निगम जोन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जलभराव नहीं हुआ हो।

लोग घरों से पानी निकालते रहे

रायपुर नगर निगम के हर जोन, मोहल्ले और कॉलोनियों में पानी भर गया। सड़के लबालब हो गईं। जयस्तंभ चौक, अनुपम गॉर्डन जैसे इलाकों में चार से पांच घंटे तक पानी भरा रहा। भारी बारिश के कारण लोग रातभर सो नहीं पाए। वह अपने घरों से पानी निकालते रहे। भाठागांव में भी पानी भरने के कारण लोगों को मुश्किलें हुईं।

विधायक ने किया निरीक्षण

भारी बारिश के कारण लोगों को हो रही मुश्किलों के बीच विधायक पुरंदर मिश्रा बाइक पर बैठकर क्षेत्र का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए की जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। विधायक के निरीक्षण में हर तरफ गंदगी और पॉलीथिन ही नजर आए।

गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

कुशालपुर इलाके के लोगों ने जलभराव की समस्या से नाराज होकर मुंबई-हावड़ा नेशनल हाईवे पर शनिवार को चक्काजाम कर दिया। लोगों ने सड़क पर बैठकर सरकार और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। कुशालपुर निवासी अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मंदिरों के सामने अवैध दुकानें बन गई हैं, नालियों पर कब्जा है और पार्षद तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनका कहना था, "छह महीने पहले सुशासन तिहार में आवेदन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)।